

Daily करेंट अफेयर्स

» 24 जून 2025



NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. प्रधानमंत्री मोदी 20-21 जून, 2025 तक दो दिवसीय दौरे के दौरान बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 24,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 से 21 जून, 2025 तक बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां उन्होंने 24,400 करोड़ रुपये से अधिक लागत की प्रमुख बुनियादी ढांचा और शासन संबंधी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया।

- 20 जून, 2025 को बिहार के सीवान में प्रधानमंत्री मोदी ने 5,200 करोड़ रुपये की लागत वाली 28 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन पहलों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है, जैसे कि नई वैशाली-देवरिया रेलवे लाइन परियोजना (400 करोड़ रुपये) और पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअल हरी झंडी दिखाना, जो भारत की 71वीं सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है, जो लगभग 7 घंटे में 384 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

- बिहार यात्रा के दौरान, उन्होंने बिहार के सारण में मरहौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित पहले निर्यात लोकोमोटिव को गिनी (पश्चिम अफ्रीका) भेजने के लिए हरी झंडी दिखाई, जिससे रेल बुनियादी ढांचे में भारत की मेक-इन-इंडिया क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ।

- 20 जून, 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा सरकार के गठन के एक साल पूरे होने

पर 18,600 करोड़ रुपये की 105 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें बुनियादी ढांचा, आवास, शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र की पहल शामिल हैं।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में 'ओडिशा विज़न डॉक्यूमेंट' का विमोचन भी किया गया, जिसके बाद भुवनेश्वर के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई और नवनिर्मित बौध जिला रेल लाइन पर पहली यात्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया।

(ii) 21 जून, 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) समारोह में भाग लिया, जिसमें स्वास्थ्य और भारत की योग परंपरा की वैश्विक पहुंच पर जोर दिया गया।

(iii) इस दो दिवसीय यात्रा में भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आवास, स्वच्छ ऊर्जा, रेल संपर्क और सार्वजनिक परिवहन सुधारों में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

2. IIT दिल्ली ने डॉक्टरेट अनुसंधान में समावेशिता में सुधार के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया।



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT दिल्ली) ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए 20 जून, 2025 को अपना पहला विशेष PhD प्रवेश

अभियान शुरू किया, ताकि कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान किया जा सके।

- यह अभियान अप्रैल 2025 में संसदीय स्थायी समिति के दौरे के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के जवाब में शुरू किया गया था, जिससे पता चला कि 2015-2024 के बीच IIT दिल्ली के PhD कार्यक्रमों में SC नामांकन केवल 8.88% से 9.69% तक था, और ST नामांकन 0.97% से 3.28% था, जो केंद्रीय संस्थानों में 15% (SC) और 7.5% (ST) के अनिवार्य आरक्षण मानदंडों से काफी नीचे है।

- यह विशेष अभियान 20 जून से 30 जून, 2025 तक खुला रहेगा, जिसमें उम्मीदवारों को IIT दिल्ली के आधिकारिक PG प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसका उद्देश्य डॉक्टरेट कार्यक्रमों में विविधता को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्यक्ष, विशेष आउटरीच के माध्यम से न्यूनतम आरक्षण प्रतिशत प्रभावी रूप से लागू हो।

- संशोधित पात्रता मानदंडों के तहत, M.Tech/ME/MD/M.Des जैसी डिग्री रखने वाले SC/ST उम्मीदवार अब न्यूनतम 55% अंक या 5.5 CGPA के साथ आवेदन कर सकते हैं, जबकि MSc/MA/MBA/MBBS जैसी डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए और साथ ही GATE (ग्रेजुएट एंटीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग), UGC-NET (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) या CSIR-NET (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) जैसे वैध राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी आवश्यक होंगी।

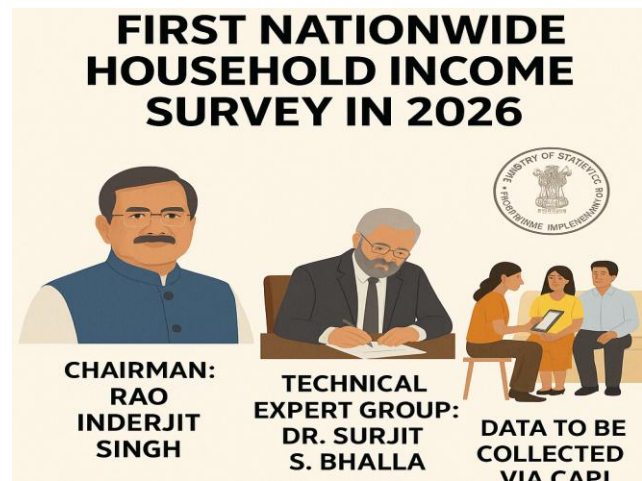
Key Points:-

(i) विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति आवेदकों को स्वीकार करें, भले ही मूल रूप से कोई सीट विज्ञापित न की गई हो, एक अतिरिक्त मॉडल के तहत। यह मौजूदा सामान्य श्रेणी के सीट आवंटन को प्रभावित किए बिना पात्र छात्रों को शामिल करने की अनुमति देता है, जिससे अन्यत्र योग्यता-आधारित प्रवेश को कम किए बिना समानता को बढ़ावा मिलता है।

(ii) इस अभियान के तहत चयन प्रक्रिया में यह अनिवार्य है कि कोई भी विभाग SC/ST उम्मीदवारों पर संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक या अतिरिक्त मानदंड नहीं लगाएगा। यह प्रणालीगत बहिष्कार से बचने और योग्यता और क्षमता के आधार पर वास्तविक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए है।

(iii) इस पहल के माध्यम से, IIT दिल्ली का लक्ष्य न केवल ऐतिहासिक असमानताओं को ठीक करना है, बल्कि अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (CFTIs) के लिए अकादमिक समानता और समावेशन की दिशा में सक्रिय, डेटा-संचालित कदम उठाने के लिए एक मिसाल कायम करना है।

3. भारत असमानता और कल्याण पर डेटा को मजबूत करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत 2026 में पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करेगा।



भारत 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत अपना पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू आय पर प्रत्यक्ष डेटा एकत्र करना है।

- इस पहल का नेतृत्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं। MoSPI ने जून 2025 में तकनीकी विशेषज्ञ समूह (Technical Expert Group - TEG) का गठन

किया है, जिसकी अध्यक्षता डॉ. सुरजीत एस. भल्ला, जो भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पूर्व कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं, कर रहे हैं। यह निर्णय कई दशकों से घरेलू आय पर सूक्ष्म और विस्तृत डेटा की मांग के चलते लिया गया है ताकि मौजूदा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Surveys - NSS) के उपभोग-आधारित आंकड़ों को पूरक किया जा सके।

- 2026 का यह सर्वेक्षण भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय प्रयास होगा जो घरेलू आय का आकलन सभी स्रोतों से करेगा—जैसे औपचारिक वेतन, अनौपचारिक आय, कृषि, स्वरोजगार, प्रेषण, किराया, पेंशन आदि। पहले के प्रयास—1950 और 60 के दशक में तथा 1983–84 के NSS राउंड में—या तो सीमित दायरे के थे या पद्धति के मामले में कमजोर थे, जिससे उपयोगी राष्ट्रीय आय वितरण डेटा नहीं मिल पाया।

- तकनीकी विशेषज्ञ समूह में प्रमुख अर्थशास्त्री शामिल हैं जैसे: अलोक कर (ISI कोलकाता), प्रो. सोनालदे देसाई (NCAER), प्रो. प्रवीण झा (JNU), प्रो. सृजित मिश्रा, तार्थकर पटनायक (NSE), राजेश शुक्ला (People Research on India's Consumer Economy), और प्रो. राम सिंह (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स)। इनका कार्य प्रश्नावली तैयार करना, सैम्पलिंग डिजाइन बनाना, अंतरराष्ट्रीय मानकों से तुल्यता सुनिश्चित करना और फील्ड संचालन के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश तैयार करना है।

Key Points:-

(i) घरेलू आय सर्वेक्षण की शुरुआत 2026 की शुरुआत में, संभावित रूप से फरवरी से जून के बीच की जा सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), जो MoSPI की एक इकाई है, फील्डवर्क को कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (CAPI) जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों की मदद से अंजाम देगा। फील्ड कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और निगरानी तंत्र तैयार किया जाएगा ताकि विशेषकर अनौपचारिक आय की सटीक गणना सुनिश्चित की जा सके।

(ii) यह सर्वेक्षण MoSPI के व्यापक सांख्यिकीय सुधारों का हिस्सा है। इसके साथ ही, MoSPI सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसे प्रमुख आंकड़ों के आधार वर्ष को 2026 की शुरुआत तक अद्यतन करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, त्रैमासिक घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण और त्रैमासिक निर्माण क्षेत्र रोजगार सर्वेक्षण जैसे अन्य सहायक सर्वेक्षण भी चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य एक समृद्ध, उच्च-आवृत्ति वाली सांख्यिकीय प्रणाली बनाना है।

(iii) नया घरेलू आय सर्वेक्षण नीति निर्माताओं को असमानता को बेहतर ढंग से समझने, PM-किसान, PM-गरीब कल्याण अन्न योजना, PMAY जैसी योजनाओं के लक्षित वितरण में सुधार करने, और प्रगतिशील कर सुधारों को दिशा देने में मदद करेगा। यह भारत को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाएगा और नीति निर्माण, कल्याण योजनाओं और आर्थिक विश्लेषण के लिए एक आवश्यक उपकरण सिद्ध होगा।

4. असम ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC/SEBC का दर्जा दिया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% पर्यवेक्षक पद आरक्षित किए।



22 जून 2025 को, असम सरकार ने दो परिवर्तनकारी नीतियों को मंजूरी दी: स्थानीय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को OBC/SEBC का दर्जा देना और अनुभवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए

महिला एवं बाल विकास विभाग में 50% पर्यवेक्षक पद आरक्षित करना।

- कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले के अनुरूप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य/सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC/SEBC) के हिस्से के रूप में आधिकारिक रूप से शामिल करने का संकल्प लिया। केवल वे लोग जो असम के स्थायी निवासी हैं, उन्हें जिला आयुक्तों द्वारा सत्यापन के बाद पहचान पत्र प्राप्त होंगे।

- इस बीच, सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्यवेक्षक स्तर के पदों के लिए आरक्षण कोटा पिछले 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो विशेष रूप से कम से कम 10 साल की सेवा वाले कार्यकर्ताओं के लिए है। शेष पदों को मानक राज्य-स्तरीय भर्ती चैनलों के माध्यम से भरा जाएगा।

- ये सुधार श्रद्धांजलि योजना के शुभारंभ के साथ मेल खाते हैं, जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों से मृतक कम आय वाले प्रवासियों को सम्मानजनक तरीके से वापस भेजना है, जो असम पुलिस विशेष शाखा के तहत 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।

Key Points:-

(i) अन्य समकालिक कैबिनेट स्वीकृतियों में शामिल हैं: राभा विकास परिषद की स्थापना; उरपद बील (1,256 हेक्टेयर) और हसिला बील (245 हेक्टेयर) को प्रस्तावित आरक्षित वन के रूप में नामित करना; हिंदुजा रिन्यूएबल्स द्वारा पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 900 करोड़ रुपये की 900 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना; और 500 करोड़ रुपये के साथ 3,000 करोड़ रुपये का असम औद्योगिक और हरित विकास कोष।

(ii) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को OBC का दर्जा देने का निर्णय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिशों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों पर आधारित है।

(iii) यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान, समान अवसर और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

इसके अधिदेश के तहत, सभी राज्य सरकारों को एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करना आवश्यक है, जिसे असम सरकार जल्द ही औपचारिक रूप से अधिसूचित करेगी।

5. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में CBIC कॉन्क्लेव में ICETAB निर्यात-निरीक्षण उपकरण का अनावरण किया।



20 जून 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) कॉन्क्लेव के दौरान, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने निर्यात जांच दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने और भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक को बढ़ावा देने के लिए ICETAB हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया।

- ICETAB डिवाइस एक सुरक्षित, टैबलेट-आधारित मोबाइल टर्मिनल है, जो सीमा शुल्क अधिकारियों को निर्यात खेप के निरीक्षण को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने, प्रति शिपमेंट चार छवियां कैप्चर करने और वास्तविक समय में रिपोर्ट अपलोड करने में सक्षम बनाता है, जिससे कागजी कार्रवाई समाप्त हो जाती है और निर्बाध व्यापार प्रक्रिया में सहायता मिलती है।

- आयात जांच में पायलट सफलता के बाद, CBIC ने 19 जून 2025 से सभी प्रमुख बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs) में ICETAB का उपयोग बढ़ा दिया है।

यह CBIC के तुरंत सीमा शुल्क और राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना 2020-25 के अनुरूप है।

● राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि ICETAB से लेन-देन की लागत कम होने और टर्नअराउंड समय कम होने, निर्यातकों के अनुभव में सुधार होने और विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत की रैंकिंग में सुधार होने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CBIC की कार्यकुशलता की प्रशंसा की - जिसमें 94.3% GSTR -3B फाइलिंग, 60 दिनों के भीतर 85% रिफंड प्रोसेसिंग और RMS के माध्यम से 86% कार्गो सुविधा पर प्रकाश डाला गया।

(ii) उन्होंने शिकायत निवारण, GST पंजीकरण, सीमा शुल्क में देरी में कमी और तेजी से जांच में और सुधार के निर्देश दिए।

(iii) यह लॉन्च भारत के कागज रहित, फेसलेस कस्टम्स विजन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो निर्यातकों के लिए तेजी से निकासी, पारदर्शिता और कम वेयरहाउसिंग देरी सुनिश्चित करता है। चल रहे प्रशिक्षण और सिस्टम अपग्रेड का उद्देश्य देश भर में ICETAB को अधिकतम रूप से अपनाना है।

6. सरकार ने किशोरियों को उभरते गैर-पारंपरिक कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए NAVYA योजना शुरू की।



भारत सरकार ने हाल ही में किशोरियों को गैर-पारंपरिक, उच्च-मांग वाली नौकरियों में कौशल विकास प्रदान करने के लिए NAVYA पायलट पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 14-18 वर्ष की लड़कियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और उद्योग संपर्क के माध्यम से सशक्त बनाना है।

● नव्या पहल - युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण - को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के संयुक्त प्रयास से 28 अगस्त 2024 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। पायलट के लिए अभिविन्यास सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के तहत कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित करता है।

● इस योजना का लक्ष्य शुरुआत में 19 राज्यों के 27 आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु की 4,000 किशोरियों को शामिल करना है। क्षेत्रीय विकास अंतराल को दूर करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत इन जिलों की पहचान की गई थी।

● उद्योग की मांग और सरकारी कौशल ढांचे के अनुरूप प्रमाणित व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए PM कौशल केंद्र (PMKKs), जन शिक्षण संस्थान (JSSs) और ITIs जैसे प्रशिक्षण साझेदारों को शामिल किया गया है।

Key Points:-

(i) NAVYA की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह व्यापक सहायता प्रणाली प्रदान करता है। नामांकित लड़कियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से ₹1,000 मासिक परिवहन भत्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में जीवन कौशल मॉड्यूल, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय शिक्षा, कानूनी जागरूकता (POCSO और कार्यस्थल सुरक्षा को कवर करना) और कैरियर परामर्श शामिल हैं - जो इसे एक समग्र सशक्तिकरण पहल बनाता है।

(ii) MSDE के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी और MWCD के सचिव श्री अनिल मलिक सहित शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने योजना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाना है, जो वर्तमान में लगभग 37% है, जो वैश्विक बेंचमार्क 55-60% के करीब है। दोनों मंत्रालयों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और 2047 तक विकसित भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नव्या को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उजागर किया।

(iii) नव्या किशोरियों को ड्रोन तकनीक, स्मार्टफोन मरम्मत, CCTV सेटअप और डिजिटल डिजाइन जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाती है - तकनीकी क्षेत्रों में लैंगिक मानदंडों को चुनौती देती है। इस कार्यक्रम की डिजिटल निगरानी स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के माध्यम से की जाती है और प्रशिक्षुता, उद्यमिता और उद्योग संपर्क की योजनाओं के साथ इसे राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

7. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया और सार्वजनिक पहुंच और योग कार्यक्रमों का शुभारंभ किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19-21 जून 2025 तक उत्तराखंड में रहेंगी, इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन में सार्वजनिक स्थलों का उद्घाटन किया, स्मारक वस्तुओं का विमोचन किया और सामूहिक योग दिवस समारोह के साथ अपनी यात्रा का समापन किया।

● 19 जून को, राष्ट्रपति मुर्मू ने 200 सीटों वाले एम्फीथिएटर का उद्घाटन किया, स्टाफ क्वार्टर, अस्तबल और बैरकों की आधारशिला रखी और राष्ट्रपति निकेतन (पूर्व में राष्ट्रपति निवास) में आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया और स्मारिका दुकान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का अनावरण किया, जो विरासत आधारित नागरिक पहुंच को रेखांकित करता है।

● उन्होंने राष्ट्रपति तपोवन के उद्घाटन में भी भाग लिया, जिसके 19 एकड़ के हिमालय-तलहटी वन पथ को 24 जून से आगंतुकों के लिए खोल दिया गया। इस एस्टेट में 117 देशी पौधों की प्रजातियाँ, 52 तितली प्रजातियाँ, 41 पक्षी प्रजातियाँ और 7 जंगली स्तनधारी हैं, जो पारिस्थितिकी को सार्वजनिक कल्याण के साथ मिलाते हैं।

● राष्ट्रपति उद्यान, 132 एकड़ का नेट-जीरो पार्क, 20 जून को शिलान्यास समारोह के साथ शुरू किया गया। विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ होने के लिए डिज़ाइन किए गए इस पार्क में पैदल चलने और साइकिल चलाने के ट्रैक, तितली गुंबद, नौका विहार की सुविधाएँ और सामुदायिक जुड़ाव के उद्देश्य से एक बड़ा एम्फीथिएटर शामिल होगा।

Key Points:-

(i) उसी दिन, राष्ट्रपति मुर्मू ने राजभवन, नैनीताल के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और निकेतन, तपोवन और उद्यान में 300 से अधिक वनस्पतियों और 170 जीवों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने वाली जैव विविधता कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तीकरण संस्थान का भी दौरा किया, जहाँ दिव्यांग बच्चों के प्रदर्शन ने उनकी आँखों में आँसू ला दिए।

(ii) यह यात्रा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपन्न हुई, जब राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून के स्टेट पुलिस लाइन मैदान में सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व किया। उनकी उपस्थिति ने राज्य-स्तरीय शासन में स्वास्थ्य, सार्वजनिक पहुँच और सांस्कृतिक समावेश के बीच के अंतरसंबंध को

उजागर किया।

(iii) ये पहल विरासत प्रबंधन में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाती हैं - एक बार निजी रहे राष्ट्रपति संपदा को सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भागीदारी, पारिस्थितिक शिक्षा और समावेशी बुनियादी ढांचे के लिए खोलना, सुलभता और स्थायी नागरिक-केंद्रित पहुंच के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करना।

8. अमित शाह ने रायपुर में 268 करोड़ रुपये की लागत वाले NFSU और CFSL परिसर की आधारशिला रखी, जिसमें इनोवेशन i-Hub का शुभारंभ भी शामिल है।



22 जून 2025 को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) परिसरों की आधारशिला का उद्घाटन किया, जिसमें युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया i-Hub भी शामिल है।

- ₹268 करोड़ के संयुक्त निवेश में ₹145 करोड़ का NFSU परिसर और ₹123 करोड़ का CFSL शामिल है, जो क्रमशः 40 एकड़ और 6-7 एकड़ में बना है। NFSU को 26 राष्ट्रीय परिसरों तक विस्तारित करने की व्यापक योजना का हिस्सा, यह पहल सालाना 32,000 फॉरेंसिक विशेषज्ञों का उत्पादन करेगी, जो वर्तमान मांग को पार कर जाएगी।

- अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि फॉरेंसिक की बढ़ती मांग के कारण NFSU से स्नातक होना नौकरी की

गारंटी के समान है। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों पर प्रकाश डाला, जिसमें सात साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थलों पर जाना अनिवार्य किया गया है, जिससे साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग को मजबूती मिलेगी।

Key Points:-

(i) छत्तीसगढ़ में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए i-Hub (इनोवेशन हब) की शुरुआत की गई। यह तकनीकी मार्गदर्शन, मेंटरशिप, वित्तीय पहुँच और इनक्यूबेशन सुविधाएँ प्रदान करता है। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि केवल विज्ञान-समर्थित आपराधिक न्याय प्रणाली ही उद्यमी भारत के समर्थन के बिना पूरी हो सकती है।

(ii) स्थानीय CFSL सुविधाओं से दिल्ली में नमूने भेजने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में चार मौजूदा राज्य प्रयोगशालाओं के साथ, नई CFSL छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में जांच क्षमता को बढ़ाती है।

(iii) अपने दो दिवसीय रायपुर दौरे के दौरान अमित शाह ने नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के लिए सात राज्यों के DGPs और ADGPs के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानसून के दौरान भी छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने नारायणपुर में BSF कैंप का दौरा किया और उग्रवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराई।

INTERNATIONAL

1. दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति ली जे-म्योंग के नेतृत्व में 64 वर्षों में पहली बार अहन ग्यू-बैक को नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया।



23 जून 2025 को, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने नागरिक नियंत्रण को पुनः स्थापित करने के लिए, अनुभवी सांसद आह ग्यू-बैक को 1961 के बाद से देश का पहला नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया।

- दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के पांच बार के सदस्य और रक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष, आह ग्यू-बैक ने हाल ही में पिछले दिसंबर के मार्शल-लॉ विवाद की संसदीय जांच का नेतृत्व किया। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ली द्वारा सेना पर लोकतांत्रिक निगरानी बहाल करने के एक प्रमुख वादे को पूरा करती है।

- यह नियुक्ति 1961 के सैन्य तख्तापलट से चली आ रही सैन्य-नियुक्त रक्षा प्रमुखों की 64 साल पुरानी परंपरा को तोड़ती है। ली की कार्यवाही को देश भर में नागरिक-प्रकृति शासन के समर्थकों द्वारा लोकतांत्रिक एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया।

- आह ग्यू-बैक का चयन ली के व्यापक मंत्रिमंडल पुनर्गठन के साथ मेल खाता है, जिसमें पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत चो ह्युन को विदेश मंत्री के रूप में और अनुभवी राजनयिक चुंग डोंग-यंग को एकीकरण मंत्रालय के कैबिनेट स्तर के लिए नामित करना शामिल है - जो कूटनीतिक विवेक की ओर नीतिगत बदलाव पर जोर देता है।

Key Points:-

(i) यह कदम पूर्व राष्ट्रपति यूं सूक-योल को अप्रैल 2025 में बर्खास्त किए जाने और पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून पर दिसंबर 2024 के मार्शल-लॉ संकट से जुड़े विद्रोह के लिए मुकदमा चलाए जाने के बाद उठाया गया है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और रक्षा नेतृत्व में नए सिरे से नागरिक निगरानी की आवश्यकता पड़ी थी।

(ii) राष्ट्रपति ली की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल असेंबली में बहुमत को देखते हुए, आह ग्यू-बैक के लिए विधायी सुनवाई एक औपचारिकता होने की उम्मीद है। उनकी अपेक्षित पुष्टि को रक्षा मामलों में नए सिरे से नागरिक प्रधानता के संकेत के रूप में देखा जाता है।

(iii) आह ग्यू-बैक की नियुक्ति क्षेत्रीय तनाव के बीच हुई है, खास तौर पर उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल परीक्षणों और प्योंगयांग, मॉस्को और बीजिंग के बीच घनिष्ठ सैन्य संबंधों के कारण। उनके नागरिक नेतृत्व से दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, सैन्य निगरानी तंत्र को नया रूप देने और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में जनता का विश्वास बहाल करने को प्राथमिकता देने की उम्मीद है, खासकर 2024 के मार्शल-लॉ घोटाले के बाद जिसने कोरियाई प्रायद्वीप में नागरिक-सैन्य विश्वास को हिला दिया था।

2. OECD ने अनुमान लगाया है कि 2035 तक वैश्विक सूखे से होने वाली हानि 35% से अधिक बढ़ जाएगी तथा तत्काल अनुकूलन के बिना 307 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष के नुकसान की चेतावनी दी है।



आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), जिसका मुख्यालय पेरिस में है और जिसका नेतृत्व महासचिव मैथियस कोरमैन करते हैं, ने 15 जून, 2025 को "वैश्विक सूखा परिदृश्य: रुझान, प्रभाव और शुष्क दुनिया के अनुकूल नीतियां" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। अध्ययन नीति, अर्थव्यवस्था और जलवायु विज्ञान के नजरिए से वैश्विक सूखा घटनाओं का व्यापक जोखिम विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

- OECD के विश्लेषण के अनुसार, 2035 तक वैश्विक स्तर पर सूखे की आर्थिक लागत में 35% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जब तक कि तत्काल अनुकूलन उपायों को लागू नहीं किया जाता। सूखे की वजह से दुनिया को पहले से ही प्रति वर्ष अनुमानित 307 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है, और आने वाले दशक में यह आंकड़ा काफी हद तक बढ़ने का अनुमान है।

- रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले दो दशकों में वैश्विक भूमि के 40% हिस्से को सूखे की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि का सामना करना पड़ा है, जिसका मुख्य कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव, बढ़ती गर्मी और वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण मिट्टी की नमी में कमी है।

Key Points:-

(i) 1900 और 2020 के बीच, सूखे से प्रभावित कुल भूमि क्षेत्र दोगुना हो गया है, जबकि 1980 के बाद से, पृथ्वी की 37% मिट्टी ने महत्वपूर्ण नमी सामग्री खो दी है, जिससे कृषि और पारिस्थितिक उत्पादकता में दीर्घकालिक गिरावट आई है।

(ii) सूखे का सीधा असर अब बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि नदी के पानी की मात्रा 40% तक कम हो सकती है और जलविद्युत उत्पादन में 25% से अधिक की गिरावट आ सकती है, जिससे ऊर्जा ग्रिड, औद्योगिक संचालन और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बाधित हो सकता है।

(iii) OECD ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी सूखा अनुकूलन नीतियां - जैसे प्रकृति-आधारित समाधान (NbS), पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, सतत जल उपयोग और बेहतर

भूमि प्रशासन - 2030 तक वार्षिक वैश्विक लाभ में \$ 10.1 ट्रिलियन उत्पन्न कर सकती हैं और निवेश किए गए प्रत्येक \$ 1 के लिए \$ 27 का रिटर्न दे सकती हैं।

BANKING & FINANCE

1. भारत ने वैश्विक बांड भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में FPI विनियमन को सरल बनाया।



18 जून 2025 को, SEBI ने केवल भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए शिथिल नियमों का एक सेट पेश किया, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक भागीदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक बॉन्ड ढांचे के साथ संरेखित करना है।

- SEBI ने नई "GS-FPI" श्रेणी शुरू की, जिसके तहत विशेष रूप से सॉवरेन बॉन्ड में निवेश करने वाले FPIs को अब निवेशक समूह के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी - जिससे केवल सरकारी निवेश के लिए अनुपालन सरल हो जाएगा।

- GS-FPIs के लिए अपने ग्राहक को जानें (KYC) अपडेट की आवृत्ति को RBI मानकों के अनुरूप बनाया गया है - जिससे विनियामक प्रयास में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अतिरिक्त, भौतिक परिवर्तनों के लिए अब 7 दिनों के बजाय 30 दिनों के भीतर प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

● SEBI अब NRIs, OCIs और निवासी भारतीयों को GS-FPI संरचनाओं में सीधे भाग लेने की अनुमति देता है, जिससे पहले के प्रतिबंध हट जाएंगे और सॉवरेन ऋण में भारतीय निवेशकों की भागीदारी बढ़ जाएगी।

Key Points:-

(i) पूर्णतः सुलभ मार्ग (FAR) के तहत G-Secs में विदेशी होल्डिंग मार्च 2025 तक ₹3 ट्रिलियन (≈US\$35billion) से अधिक हो गई है - जो मार्च 2024 में ₹1.74 ट्रिलियन से लगभग दोगुनी है। जेपी मॉर्गन और FTSE रसेल जैसे वैश्विक सूचकांकों में समावेशन इन प्रवाहों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण रहा है।

(ii) यह सुधार SEBI की 18 जून 2025 की बोर्ड बैठक का हिस्सा था, जिसमें स्टार्टअप ESOP मानदंडों में ढील दी गई, PSU डीलिंग को सरल बनाया गया और AIF/AIF सह-निवेश ढांचे में सुधार किया गया - जो लचीलेपन और वैश्विक तत्परता का संकेत देता है।

(iii) FPI अनुपालन को सॉवरेन बांड जोखिमों और आसान प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर, SEBI का लक्ष्य भारत के ऋण बाजारों को गहरा करना, उधार लेने की लागत कम करना और स्थिर वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना है - जिससे राजकोषीय इंजन और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी।



भारत सरकार ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माध्यम से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को आधार वर्ष को संशोधित कर 2024 करने और बाजार कवरेज को ताज़ा करने का निर्णय लिया है, जिसका लक्ष्य 2026 से मुद्रास्फीति पर अधिक सटीक नज़र रखना है।

● MoSPI (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES 2022-23) का उपयोग करके 2012 से 2024 तक CPI आधार को अपडेट करने का प्रस्ताव करता है। यह वर्तमान व्यय के आधार पर भार को ताज़ा करेगा, जिसमें ~2,900 बाज़ार शामिल होंगे - जो पहले ~2,300 से उल्लेखनीय वृद्धि है।

● वर्तमान CPI में आधुनिक उपभोग के प्रमुख रुझान शामिल नहीं हैं - खास तौर पर ई-कॉमर्स, डिजिटल सब्सक्रिप्शन और राइड-हेलिंग का उपयोग। संशोधन में PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) वस्तुओं और अन्य गैर-मौद्रिक लेन-देन के उपचार पर भी पुनर्विचार किया गया है, जो स्वच्छ आर्थिक माप के लिए आईएमएफ के मार्गदर्शन के अनुरूप है।

● बिस्वनाथ गोल्डर (NSO) की अगुआई वाली एक उच्च स्तरीय समिति इस प्रक्रिया की देखरेख कर रही है। डेटा को मान्य करने और मौजूदा श्रृंखला की निरंतरता सुनिश्चित करने के बाद, 2026-27 के बीच नया आधार वर्ष लागू होने की उम्मीद है। CPI GDP और IIP के लिए नए आधार वर्षों के साथ संरेखित होगा।

Key Points:-

ECONOMY & BUSINESS

1. भारत मुद्रास्फीति की सटीकता में सुधार लाने और आधुनिक उपभोग को प्रतिबिंबित करने के लिए CPI बास्केट और आधार वर्ष को संशोधित करेगा।

(i) RBI CPU को अपने प्राथमिक मुद्रास्फीति बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है - जिसका लक्ष्य $4 \pm 2\%$ है। बढ़ी हुई सटीकता से मौद्रिक नीति, सब्सिडी डिजाइन और पेंशन और वेतन के सूचकांक को बेहतर ढंग से सूचित किया जा सकेगा, जिससे कल्याण लक्ष्यीकरण में सुधार होगा।

(ii) हर 5-7 साल में आधार वर्ष बदलना सबसे अच्छा अंतरराष्ट्रीय अभ्यास है। अपडेट किए गए सूचकांक उभरते उपभोग पैटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं - जैसे कि डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर बढ़ता खर्च, जो मुद्रास्फीति के आंकड़ों को वर्तमान जीवनशैली के साथ संरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

(iii) 2023-24 के लिए HCES सर्वेक्षण दौर आइटम भार को ठीक करने के लिए चल रहे हैं। MoSPI अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों से परामर्श करेगा, उसके बाद डेटा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक सुचारू माइग्रेशन रणनीति तैयार करेगा - वास्तविक GDP, WPI और CPI रुझानों जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों में व्यवधानों को कम करना।

2. स्थिरता और वैश्विक मांग के कारण वित्त वर्ष 26 की शुरुआत में भारत का कॉफी निर्यात 25% बढ़ा।



वित्त वर्ष 2025-26 के पहले महीनों में, भारतीय कॉफी निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25% की वृद्धि हुई

है, जो 2024-25 में 40% वार्षिक वृद्धि के बीच भारतीय बीन्स की वैश्विक मांग को रेखांकित करता है।

● भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 1.803 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 40.2% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की शुरुआत में यह मजबूत प्रवृत्ति जारी रही, जिसमें 25% की और वृद्धि हुई।

● भारत 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 3.5%) और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक (लगभग 5% हिस्सा) है। प्रमुख बाजारों में यूरोप, इटली, जर्मनी, बेल्जियम और जापान, कोरिया और मध्य पूर्व शामिल हैं।

● कॉफी बोर्ड छाया में उगाई गई, हाथ से चुनी गई और धूप में सुखाई गई कॉफी को आक्रामक तरीके से बढ़ावा दे रहा है। इसने पांच क्षेत्रीय और दो विशेष किस्मों के लिए भौगोलिक संकेत टैग भी हासिल किए हैं ताकि विशिष्ट गुणों को उजागर किया जा सके।

Key Points:-

(i) बेंगलुरु में नया अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC-CCRI-CED) 63 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करता है और 3,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर चुका है, जिससे मूल्य-वर्धित क्षेत्रों में वृद्धि में सहायता मिलती है। कॉफी बोर्ड मूल्य-वर्धित मशीनरी (₹15 लाख तक) पर सब्सिडी भी देता है और डिजिटल RCMC, उत्पत्ति और निर्यात परमिट जारी करता है।

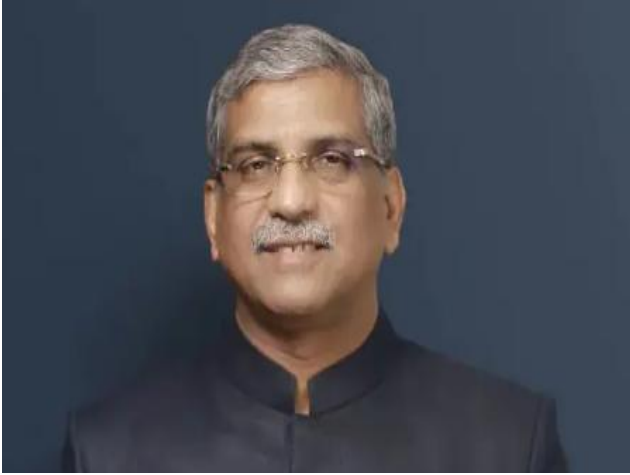
(ii) ब्राजील/वियतनाम में वैश्विक आपूर्ति बाधाओं ने भारतीय रोबस्टा की मांग को बढ़ावा दिया है, जो अब अरेबिका के मुकाबले 70:30 के अनुपात में हावी है। रोबस्टा निर्यात में रिकॉर्ड कीमतें देखी गई हैं - 23 हजार रुपये/50 किलोग्राम जबकि अरेबिका 28 हजार रुपये पर है - जो मजबूत वैश्विक प्रीमियम का संकेत है।

(iii) कॉफी बोर्ड के लिए वित्त वर्ष 26 में आवंटन बढ़ाकर ₹280 करोड़ (+12%) कर दिया गया है, और यूरोपीय संघ का वनों की कटाई का अनुपालन दिसंबर 2025 में प्रभावी

हो रहा है, भारत वैश्विक बाज़ार मानकों को पूरा करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी करके ट्रेसबिलिटी और कार्बन-फुटप्रिंट मैपिंग को बढ़ा रहा है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. बेंगलुरु में 27वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान के. पॉल थॉमस को Sa-Dhan का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।



जून 2025 में, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कदमबेलिल (के.) पॉल थॉमस को माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए भारत के शीर्ष स्व-नियामक संगठन (SRO) सा-धन का नया अध्यक्ष चुना गया।

- यह चुनाव कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित सा-धन की 27वीं वार्षिक आम सभा (AGM) के दौरान हुआ।
- वार्षिक आम बैठक में नए शासी निकाय सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिनमें जी. किरण कुमार (स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज), राहुल गुप्ता (अवंती फाइनेंस), जगदीश रामदुगु (प्रगति फिनसर्व) और प्रवीण थिगले (फिंगल मैनेजमेंट सर्विसेज) शामिल हैं।
- के. पॉल थॉमस, जो केरल के त्रिशूर से हैं, समुदाय-आधारित बैंकिंग और वित्तीय समावेशन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं।

Key Points:-

(i) के. पॉल थॉमस ने 1992 में इवेंजेलिकल सोशल एक्शन

फोरम (ESAF) की स्थापना की, जो ESAF माइक्रोफाइनेंस में परिवर्तित हो गया और बाद में 2017 में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF SFB) बन गया, जो भारत के अग्रणी समावेशी वित्त संस्थानों में से एक है।

(ii) उनके नेतृत्व में, ESAF ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज़ (GABV) का पहला भारतीय सदस्य बना और इसे दो बार यूरोपीय माइक्रोफाइनेंस पुरस्कार के लिए चुना गया।

(iii) उन्हें विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में वंचित समुदायों के लिए नैतिक, टिकाऊ और मूल्य-संचालित वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

SPORTS

1. सिंगापुर में तीरंदाजी एशिया कप 2025 चरण 2 में भारत 9 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है।



भारत की अंडर-21 तीरंदाजी टीम ने सिंगापुर में आयोजित एशिया कप तीरंदाजी 2025 स्टेज-2 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक (2 स्वर्ण, 6 रजत, 1 कांस्य) जीते। यह प्रतियोगिता 15 से 20 जून 2025 तक बुकिट गोम्बाक स्टेडियम, सिंगापुर में आयोजित हुई।

• इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्ल्ड आर्चरी एशिया (WAA) द्वारा किया गया था। भारत ने इंडोनेशिया (5 पदक) और कज़ाकिस्तान (3 पदक) को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में

21 देशों के 200 से अधिक तीरंदाजों ने भाग लिया, जिससे भारत की सफलता और भी महत्वपूर्ण बन गई।

- भारत को कुल 2 स्वर्ण पदक मिले, जो पुरुषों और महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धाओं में आए। पूरी टीम अंडर-21 खिलाड़ियों से बनी थी, जिन्होंने टीम और व्यक्तिगत दोनों श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि भारत को पांच फाइनल मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा।

- पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के कुशल दलाल ने ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ माहोन को 149-143 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह कुशल का लगातार दूसरा एशिया कप स्वर्ण पदक था; उन्होंने इससे पहले 2025 में बैकॉक में भी स्वर्ण जीता था।

Key Points:-

(i) महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में तेजल राजेंद्र साल्वे ने शन्मुख नागा साई बुड्डे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह मुकाबला पूरी तरह से भारतीय था, जिसमें तेजल ने 146-144 से जीत दर्ज की और अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिरता साबित की।

(ii) भारत की कंपाउंड महिला टीम जिसमें तेजल साल्वे, शन्मुख बुड्डे और तनिष्का मालवणकर ठोकल शामिल थीं, ने 2,101 अंकों के साथ नया अंडर-21 विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड पहले के 2,076 अंकों (2023) को तोड़ते हुए स्थापित किया गया, जो भारत के जूनियर तीरंदाजों की ताकत और तैयारी को दर्शाता है।

(iii) हालांकि भारत को पांच फाइनल में हार झेलनी पड़ी, फिर भी कुल प्रदर्शन के आधार पर भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। भारतीय तीरंदाजी संघ (AAI) ने इस युवा टीम के प्रदर्शन की सराहना की और इसे आगामी एशियन गेम्स और युवा ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए एक अहम कदम बताया।

2. ऋषभ पंत दोहरे टेस्ट शतक के साथ पहले भारतीय विकेटकीपर बनकर इतिहास रच दिया।



23 जून 2025 को हेडिंग्ले, लीड्स में, ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जुड़वां शतक (134 और 118) हासिल किए, जो भारतीय क्रिकेट में एक ऐतिहासिक क्षण था।

- पहली पारी में पंत के शानदार प्रदर्शन में 178 गेंदों पर 12 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 134 रन की तूफानी पारी शामिल थी, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी पारी में 118 रन बनाकर उनका फॉर्म जारी रहा, जो उनकी असाधारण बल्लेबाजी कौशल और लचीलेपन को दर्शाता है।

- इस उपलब्धि ने उन्हें टेस्ट इतिहास में जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर के बाद 2001 में एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले केवल दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज और इंग्लिश धरती पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बना दिया।

- विशेष रूप से, पंत के संचयी 252 रनों ने श्रीलंका के महान कुमार संगकारा के एशियाई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जहां संगकारा ने एक मैच में 244 रन बनाए थे, जिससे पंत के दोहरे शतक और भी महत्वपूर्ण हो गए।

Key Points:-

(i) क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने पंत से अपने दूसरे

शतक के बाद अपनी खास कलाबाजी का जश्न मनाने का आग्रह किया, जिससे इस ऐतिहासिक उपलब्धि में एक हल्का-फुल्का व्यक्तिगत स्पर्श जुड़ गया। पंत ने इस उपलब्धि के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए विनम्रतापूर्वक मना कर दिया।

(ii) पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पंत की उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए उन्हें "भारत का अब तक का सबसे महान विकेटकीपर-बल्लेबाज" कहा, उनके सात टेस्ट शतकों में इस प्रदर्शन को उजागर किया और इसे खेल बदलने वाला क्षण बताया।

(iii) पंत के दोहरे शतकों की मदद से भारत ने चौथी पारी में 371 रनों का लक्ष्य रखा, जिससे इंग्लैंड दबाव में आ गया और स्टंप तक उसका स्कोर 21/0 हो गया तथा पांचवें दिन का खेल रोमांचक समापन की ओर अग्रसर हो गया।

● यह शिखर सम्मेलन 1975 में जी7 (G7) साझेदारी की शुरुआत के बाद उसकी 50वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।

● शिखर सम्मेलन ने G7 सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया, जिसकी शुरुआत 1975 में फ्रांस में हुई रैम्बोइलेट बैठक से हुई थी। इसने दुनिया की प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मुद्दों, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया। 52वां जी7 शिखर सम्मेलन जून 2026 में एवियन-लेस-बैंस, हाउते-सावोई, फ्रांस में होने वाला है।

● 2025 G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वालों में मार्क कार्नी (कनाडा), इमैनुएल मैक्रोन (फ्रांस), फ्रेडरिक मर्ज़ (जर्मनी), जियोर्जिया मेलोनी (इटली), शिगेरु इशिबा (जापान), कीर स्टारमर (UK) जैसे शीर्ष वैश्विक नेता शामिल थे।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. कनाडा 2025 में अल्बर्टा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो G7 साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा।



51वां G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून, 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित कनानसकीस में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कनाडा के G7 प्रेसीडेंसी के तहत की गई और इसकी मेजबानी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की।

Key Points:-

(i) आउटरीच सत्रों के लिए आमंत्रित अतिथि राष्ट्रों में शामिल थे: भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और दक्षिण अफ्रीका।

(ii) भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 जून, 2025 को कनाडा की यात्रा पर गए और जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। यह G7 सम्मेलन में उनकी छठी उपस्थिति थी।

(iii) शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय लचीलापन और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें नेताओं ने विविध स्रोतों के माध्यम से दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने पर एक घोषणा को अपनाया। उल्लेखनीय रूप से, कनाडा और यूरोपीय संघ ने ऊर्जा लचीलापन भागीदारी (ERP) के तहत परियोजनाओं के लिए 2.3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का वचन दिया, जबकि अमेरिका ने कम कार्बन खनिज सोर्सिंग का समर्थन करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर का वचन दिया।

IMPORTANT DAYS

1. 23 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस' मनाया गया, विधवाओं के अधिकारों और चुनौतियों पर दिया गया वैश्विक ध्यान।



संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 23 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विधवाओं की आवाज़ को सशक्त बनाना और उनके सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकार संबंधी समस्याओं को उजागर करना है, विशेषकर विकासशील देशों में।

- (i) यह दिन हर वर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य विधवाओं के जीवन स्तर को सुधारने हेतु कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर बल देना है। यह विधवाओं और उनके बच्चों के लिए न्याय, समानता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की अपील करता है।

- (ii) अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में यूके आधारित लोम्बा फाउंडेशन (Loomba Foundation) द्वारा की गई थी। यह संगठन विधवाओं के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करता है, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। यह संगठन विधवाओं के मुद्दों को वैश्विक नीति में शामिल करने के लिए काम कर रहा है।

- (iii) संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने इस दिवस को औपचारिक मान्यता 21 दिसंबर 2010 को पारित संकल्प A/RES/65/189 के माध्यम से दी। इस प्रस्ताव के अनुसार,

23 जून को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ताकि विधवाओं की उपेक्षा और भेदभाव के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता मिल सके।

Key Points:-

(i) संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त पहला विधवा दिवस 23 जून 2011 को मनाया गया था। इस अवसर पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के राजनयिकों, संगठनों और विधवा अधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

(ii) संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) के अनुसार, विश्वभर की कई विधवाएं अब भी संपत्ति से बेदखली, सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और आर्थिक अभाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही हैं। 2025 की थीम ने पुनः यह आह्वान किया कि विधवाओं के लिए आंकड़ा-आधारित नीतियां, कानूनी सहायता, शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

(iii) इस वर्ष की पहल में संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों और नागरिक समाज से आग्रह किया कि वे विधवाओं के लिए ऐसे राष्ट्रीय ढांचे तैयार करें जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) और लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी) के अनुरूप हों और उन्हें गरिमापूर्ण व न्यायपूर्ण जीवन प्रदान कर सकें।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. DRDO ने सशस्त्र बलों के 'मेक-इन-इंडिया' अभियान को मजबूत करने के लिए आपातकालीन खरीद के लिए 28 स्वदेशी हथियारों की पेशकश की।



जून 2025 में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा त्वरित आपातकालीन खरीद के लिए 28 घरेलू हथियार प्रणालियों के चयन की घोषणा की - जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन-रोधी तकनीक तक शामिल हैं।

- DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने हाइपरसोनिक मिसाइलों, अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस वेरिएंट, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा और काउंटर-ड्रोन सिस्टम, मोबाइल आर्टिलरी और हल्के टैंकों की एक विविध सूची का अनावरण किया।

- ये पेशकश आपातकालीन खरीद तंत्र के अनुरूप हैं - जो स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों के त्वरित अधिग्रहण के लिए अनुमोदित हैं - जिसके तहत 300 करोड़ रुपये तक के अनुबंध और 6-12 महीनों के भीतर डिलीवरी की अनुमति है।

- स्वदेशी प्रणालियों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी समकक्ष हथियारों को पीछे छोड़ दिया। DRDO के अध्यक्ष ने पुष्टि की कि नागस्त-1 लोडिंग म्यूनिशन और ब्रह्मोस प्रोपल्शन इकाइयों जैसी प्रणालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे घरेलू तकनीक में विश्वास मजबूत हुआ।

Key Points:-

(i) DRDO ने उत्पादन बढ़ाने और मेक-इन-इंडिया लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में ब्रह्मोस एयरोस्पेस और सोलर डिफेंस एंड

एयरोस्पेस लिमिटेड जैसे निजी इंटीग्रेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

(ii) भारत का लक्ष्य VSHORAD (बहुत कम दूरी की वायु रक्षा), MPTAGM (मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल) और उन्नत टारपीडो जैसी प्रणालियों को तेजी से अपनाकर महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरना है - ये सभी 28-आइटम की सूची का हिस्सा हैं जिन्हें तत्काल अपनाने का इरादा है।

(iii) प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप, यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। स्वदेशी चैनलों के माध्यम से ₹7,300 करोड़ मूल्य के आपातकालीन ऑर्डर पहले से ही जारी हैं, DRDO भारत की रक्षा खरीद रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।

2. BSNL हैदराबाद में स्वदेशी सिम-रहित क्वांटम 5G FWA सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय ऑपरेटर बन गया।



18 जून, 2025 को, BSNL ने हैदराबाद के अमीरपेट एक्सचेंज में भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी क्वांटम 5G FWA (फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस) सेवा का सॉफ्ट-लॉन्च किया। BSNL/MTNL के CMD श्री ए रॉबर्ट जे रवि द्वारा उद्घाटन किया गया, यह लॉन्च भारत के 5G रोलआउट में एक रणनीतिक मील का पत्थर है - जिसमें स्वदेशी तकनीक के साथ सिम-लेस, डायरेक्ट-टू-डिवाइस 5G रेडियो शामिल है।

- इस लॉन्च के साथ BSNL सिम-लेस 5G आर्किटेक्चर पेश करने वाला पहला भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है,

जहां उपयोगकर्ता का डिवाइस बिना किसी भौतिक सिम के सीधे कनेक्ट होता है। BSNL के डायरेक्ट-टू-डिवाइस प्लेटफॉर्म पर निर्मित, यह समाधान सिम कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करता है, 5G प्रमाणीकरण में नवाचार को प्रदर्शित करता है और भारत को वैश्विक दूरसंचार मानकों की ओर ले जाता है।

- क्वांटम 5G FWA को पूरी तरह से स्वदेशी स्टैक के साथ विकसित किया गया है - जिसमें कोर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) और ग्राहक परिसर उपकरण (CPE) शामिल हैं - जिसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिज़ाइन और एकीकृत किया गया है। सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का उत्पादन भारतीय विक्रेताओं द्वारा किया गया था, जो दूरसंचार आत्मनिर्भरता और उन्नत कनेक्टिविटी समाधानों में घरेलू क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित थे।

- हैदराबाद में सॉफ्ट लॉन्च ने गीगाबिट-क्लास प्रदर्शन दिया, जिसमें 980 Mbps डाउनलोड और 140 Mbps अपलोड स्पीड प्राप्त हुई, जिसमें सब-10ms विलंबता थी। ये स्पीड अल्ट्रा-HD स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग और रियल-टाइम वीडियो सहयोग का समर्थन करती हैं। BSNL का वायरलेस इंस्टॉलेशन मॉडल फाइबर ट्रेचिंग की आवश्यकता को भी समाप्त करता है, जिससे शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तैनाती तेज और लागत-कुशल हो जाती है।

Key Points:-

(i) BSNL ने एक स्व-स्थापित गेटवे तैनात किया है जो मौजूदा BSNL टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके हैदराबाद के 85% घरों से जुड़ता है। यह त्वरित-स्थापना विधि ऑपरेटर को पारंपरिक केबल परिनियोजन को बायपास करने की अनुमति देती है, जिससे घरों और कार्यालयों में तत्काल ब्रॉडबैंड पहुँच सक्षम होती है, जिससे भारत के सबसे डिजिटल-तैयार शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में ब्रॉडबैंड पैठ में तेजी आती है।

(ii) रोलआउट रोडमैप में बेंगलुरु, पांडिचेरी, विशाखापत्तनम,

पुणे, ग्वालियर और चंडीगढ़ में पायलट विस्तार शामिल है, जिसका फील्ड ट्रायल सितंबर 2025 तक शुरू हो जाएगा। BSNL ने 100 Mbps के लिए 999 रुपये प्रति माह और 300 Mbps के लिए 1499 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाले परिचयात्मक टैरिफ की घोषणा की है - जिससे देश भर में आवासीय और वाणिज्यिक दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए सस्ती, उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड उपलब्ध होगी।

(iii) BSNL उसी 5G SA कोर का उपयोग करके अपना एंटरप्राइज एज-क्लाउड समाधान भी तैनात करेगा, जिससे MSMEs और औद्योगिक IoT के लिए एसएलए-आधारित कनेक्टिविटी सक्षम होगी। यह परियोजना स्मार्ट विनिर्माण, दूरस्थ संचालन और नेटवर्क स्लाइसिंग का समर्थन करेगी। पायलट शहरों से फीडबैक के बाद राष्ट्रव्यापी रोलआउट शुरू होगा, जिससे BSNL भारत की स्वदेशी 5G क्रांति में अग्रणी बन जाएगा।

3. SSLV के निर्माण और संचालन के लिए ISRO से 511 करोड़ रुपये का ToT सौदा हासिल करने के बाद HAL भारत का तीसरा रॉकेट निर्माता बन गया।



बेंगलुरु स्थित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को इसरो से ₹511 करोड़ की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) डील प्राप्त हुई है, जिसके तहत HAL अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) का निर्माण और संचालन करेगा। इसके साथ ही HAL भारत का तीसरा रॉकेट निर्माता बन गया है।

- इस डील के माध्यम से HAL भारत की तीसरी रॉकेट निर्माण कंपनी बन गई है। इससे पहले निजी कंपनियों में स्काईरूट एयरोस्पेस (तेलंगाना) और अग्रिकुल कॉसमॉस (तमिलनाडु) यह स्थान प्राप्त कर चुके हैं। यह ISRO द्वारा किसी भारतीय कंपनी को किया गया पहला पूर्ण रॉकेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो देश की स्वदेशी अंतरिक्ष निर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है।

- ₹511 करोड़ की इस ToT डील के तहत HAL को SSLV के डिज़ाइन, निर्माण, एकीकरण और लॉन्च संचालन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। HAL का चयन तीन-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. विजय राघवन और पूर्व ISRO निदेशक सुरेश ने की।

- इस समझौते के अंतर्गत ISRO अगले दो वर्षों तक HAL को SSLV तकनीक, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद HAL हर वर्ष 6 से 12 SSLV को स्वतंत्र रूप से तैयार कर सकेगा। यह चरणबद्ध रूपांतरण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और HAL की तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगा।

Key Points:-

(i) SSLV के व्यावसायिक प्रक्षेपण कार्यों को ISRO की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा संभाला जाएगा। वहीं, प्रक्षेपण के नियामक और प्राधिकरण संबंधी कार्य IN-SPACe (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर) द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद (गुजरात) में स्थित है।

(ii) SSLV एक तीन-चरणीय ठोस ईंधन रॉकेट है, जिसकी लंबाई 34 मीटर और व्यास 2 मीटर है। यह 500 किलोग्राम तक के पेलोड को 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में पहुंचाने में सक्षम है। यह छोटे उपग्रहों और स्टार्टअप्स के लिए शीघ्र प्रक्षेपण की आवश्यकता को पूरा करता है।

(iii) यह सहयोग भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूती प्रदान करता है। HAL जैसे

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को लॉन्च वाहन निर्माण में शामिल करने से देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ISRO एवं निजी स्टार्टअप्स के साथ संतुलित अंतरिक्ष लॉन्च प्रणाली का विकास होगा।

Static GK

Andhra Pradesh	मुख्यमंत्री: एन. चंद्रबाबू नायडू	राज्यपाल: एस. अब्दुल नज़ीर
MoSPI	मंत्री: राव इंद्रजीत सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Assam	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा	राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
South Korea	अध्यक्ष: ली जे-म्यांग	मुद्रा: दक्षिण कोरियाई वोन
Canada	प्रधान मंत्री: मार्क कार्नी	राजधानी: ओटावा
the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)	महासचिव : मैथियास ह्यूबर्ट पॉल कॉर्मन	मुख्यालय : पेरिस, फ्रांस
DRDO	अध्यक्ष: समीर वी. कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली
SEBI	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे	मुख्यालय: मुंबई
Sa-Dhan	स्थापित: 1999	मुख्यालय: नई दिल्ली
BSNL	स्थापना: 2000	मुख्यालय: नई दिल्ली
Uttarakhand	मुख्यमंत्री (CM) : पुष्कर सिंह	राज्यपाल : गुरमित सिंह

	धामी	
HAL	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : डॉ. डी.के. सुनील	मुख्यालय : बेंगलुरु, कर्नाटक
Coffee Board of India	अध्यक्ष: श्री एम. जे. दिनेश	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव: के.जी. जगदीश